सागर के केसली में 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन और लोकार्पण

मातृ शक्ति का आशीर्वाद बना संबल, विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश : मोहन

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुन्देलखंड की धरती ने अपने गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। बुन्देलखंड के वीरों ने अतीत से लेकर आज तक देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। मातृ शक्ति का आशीर्वाद सरकार के लिए संबल प्रदान कर रहा है। उनकी सहभागिता एवं नेतृत्व के माध्यम से आज मध्यप्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित बनाने में अपना सहयोग दे रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर जिले के केसली में रविवार को आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लगभग 190.85 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करते हुए शिलापट्टिका का अनावरण किया। इसमें लगभग 68.83 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 25 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 122.02 करोड़ रुपये की लागत से 28 कार्यों का भूमि-पूजन कर लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त भी जारी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मातृ शक्ति का सशक्तिकरण और उनका नेतृत्व वर्तमान की आवश्यकता है और सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार का कार्य कर रही है। लाड़ली बहना योजना तीसरे साल में प्रवेश कर रही है, जिसके माध्यम से प्रत्येक माह बहनों के बैंक खातों में राशि प्रदान की जा रही है। लाड़ली बहना योजना हमारी माताओं बहनों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इससे सुखद बात क्या हो सकती है कि लाड़ली बहना योजना से मिली राशि से बहनें अपने परिवार के संचालन में सहयोग कर रही हैं। यह उनका समर्पण है, उनका अपना त्याग है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक स्तर में बड़ा सुधार आया है। उन्होंने कहा कि बहनों एवं मातृशक्ति के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। आज उनके मन में शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का विश्वास बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष मना रही है। इसमें किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक करने का है। जब किसान के खेत में पानी आता है तो उसके साथ उसके जीवन में बदलाव आता है। दुग्ध उत्पादन को बढावा देने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। जहाँ सरकार ने गौमाताओं के लिए प्रतिदिन खर्च को बढाया है, वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार योजनाएं चला रही है एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान दे रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री पद रहने का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोकल्याणकारी योजनओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास, स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। धरती आबा योजना के माध्यम से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए जा रहे है। आवासहीनों को आवास, भूमिहीनों को भूमि के पट्टे मिल रहे हैं और महिलाओं को संबल मिल रहा है।

लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं की समाज एवं परिवार में स्थिति मजबूत हुई है। धरती आबा योजना के माध्यम से जनजातीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि सरकार द्वारा आपके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, पात्रता अनुसार उनका लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केसली में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने केसली में सांदीपनि विद्यालय सेकण्ड फेज का कार्य प्रारंभ करने, शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकण्डरी स्कूल तक उन्नयन करने, शासकीय हाई स्कूल देवरी, नाहरमऊ, नन्ही देवरी का उन्नयन करने, कृषि उपज मंडी केसली का नाम रानी अवंतिबाई के नाम पर रखने, देवरी में 100 बिस्तरों का अस्पताल स्टाफ सहित प्रारंभ करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने केसली क्षेत्र में थावरी जलाशय (लागत लगभग 550 करोड़) की योजना को स्वीकृति दी तथा कहा कि किसानों की इस बहुप्रतीक्षित मांग से क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री ने देवरी में प्याज और लहसुन की खरीदी के लिए मंडी में खरीदी केन्द्र बनाने की घोषणा की। शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय तथा कला संकाय में राजनीति विषय का आरंभ करने, केसली महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने, देवरी नगर का नाम देवपुरी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप देवखंडेराव मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ग्राम पंचायत गौरझामर एवं ग्राम पंचायत केसली को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सागर जिले के देवरी विधानसभा अंतर्गत केसली ब्लॉक में यह पहला और महत्वपूर्ण आगमन था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में उनका यह पहला दौरा था, जिसे लेकर स्थानीय जनता और प्रशासन में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रैंप से लाड़ली बहनों के बीच पहुंचकर पुष्पवर्षा की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कार्यक्रम में उपस्थित लाड़ली बहनों में उत्साह एवं उल्लास देखने को मिला। इस अवसर पर महिलाओं ने धन्यवाद लाड़ले भैया लिखे प्लेकार्ड प्रदर्शित कर मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सागर जिले के केसली में एक बेहद अनूठे और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहाँ लाड़ली बहनों के साथ पारंपरिक खेल सितोलिया (पिट्टू) खेलकर लाड़ली बहना खेल सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने न केवल कार्यक्रम की शुरुआत की, बल्कि खुद मैदान में उतरकर खेलों में सक्रिय सहभागिता की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर और उन्हें बच्चों व युवाओं की तरह पारंपरिक खेल खेलते देख वहाँ मौजूद महिलाओं और लाड़ली बहनों का उत्साह दोगुना हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को स्वस्थ, जागरूक और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

हितग्राहियों को वितरित किए हितलाभ मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न हितग्राहियों को मंच से लाभान्वित किया। कार्यक्रम में शिक्षा, आजीविका संवर्धन एवं प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रोत्साहन राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय उत्पादों पर केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विभागों के प्रयासों की सराहना की। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहनों से जो वादा किया था, वह निभाया है। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को सशक्त किया जा रहा है, उनकी उपज को सरकारी दाम पर खरीदा जा रहा है। इस वर्ष 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि पहली बार मध्यप्रदेश में किसानों की भूमि का अधिग्रहण होने पर उसका चार गुना मुआवजा किसानों को मिलेगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश सहित बुन्देलखंड में औद्योगिक विकास किया जा रहा है। उन्होंने शबरी माता के नाम पर माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के भूमि-पूजन पर आभार भी प्रकट किया। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल केसली का नहीं, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश का है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश में गेहूं खरीदने में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 1064 मार्गों पर 5,200 से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा। इससे उन मार्गों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिन मार्गों से प्राइवेट बस संचालक बसों का संचालन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के देवरी विधानसभा में पहली बार आगमन पर देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से गरीब, महिला, किसान, युवा का कल्याण हो रहा है। इस अवसर पर सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े, पूर्व मंत्री एवं विधायक रहली गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री एवं विधायक खुरई भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, बंडा विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी, बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे, महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार, श्रीमती रानी कुशवाहा, संभागायुक्त अनिल सुचारी, डीआईजी एस एस चौहान, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

डीजल का काला खेल बेनकाब 2640 लीटर अवैध भंडारण जब्त

इधर गुस्सा उतारने सड़क पर उतर रहे किसान

सच संवाददाता ॥ सीहोर

सीहोर जिले में डीजल की किल्लत अब सिर्फ आपूर्ति का मामला नहीं रह गया है। यह अवैध कारोबार, प्रशासनिक कार्रवाई और किसानों के बढ़ते आक्रोश का बड़ा मुद्दा बन चुका है। भैरूंदा क्षेत्र के ग्राम छीपानेर में प्रशासन ने रविवार रात को एक घर से 2640 लीडर डीजल का अवैध भंडारण जब्त किया है। इस कार्रवाई ने जहां डीजल के काले कारोबार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बोवनी की तैयारी में जुटे किसानों का गुस्सा भी सड़कों पर फूटने लगा है।

भैरूंदा एसडीएम सुधीर कुशवाहा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम छीपानेर में एक मकान में बड़ी मात्रा में डीजल का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल जांच के निर्देश दिए। इसके बाद नायब तहसीलदार आरती सोलंकी, राजस्व निरीक्षक गोपालपुर और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच शुरू होते ही टीम के सामने जो तस्वीर आई, उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया। मकान के भीतर एक-दो नहीं बल्कि 12 बड़ी टंकियों में डीजल

भरा हुआ मिला। प्रत्येक टंकी में करीब 220 किलोग्राम डीजल था। कुल मिलाकर 2640 किलोग्राम डीजल का भंडारण पाया गया।

मौके पर मौजूद शिवम गंधवाने पिता रामचन्द्र गंधवाने से पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि डीजल सीहोर स्थित गैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा गया था और इसे ग्राहकों को बेचने के उद्देश्य से रखा गया था। प्रशासन ने इसे नियमों के विरुद्ध माना और पूरे डीजल को जब्त कर लिया। जब्त डीजल को सुरक्षित रखने के लिए छीपानेर किसान सेवा केन्द्र की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

उधर जिले में डीजल की कमी से परेशान किसानों का गुस्सा भी चरम पर पहुंच गया। बोवनी का समय शुरू होने के कारण खेतों में ट्रैक्टर, पंप और कृषि उपकरणों की मांग बढ़ गई है। ऐसे समय पर डीजल की कमी किसानों के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। शनिवार को कई किसान सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर डीजल लेने पहुंचे थे। आरोप है कि पूरे दिन इंतजार के बावजूद पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिला।

इससे नाराज किसान शाम को रेहटी-भैरूंदा मार्ग पर कृषि फार्म के सामने एकत्र हो गए और सड़क जाम कर दी।इस पूरे मामले के बीच रविवार रात बिजोरी की पूर्व सरपंच दीपेश राठौर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीहोर के एक पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में केनों में डीजल दिया जा रहा था, जबकि किसानों को सीमित मात्रा में डीजल देने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वयं एक पिकअप वाहन में 100 से अधिक केन भरकर ले जाते हुए देखे। उनके इस आरोप के बाद डीजल वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार

किसानों के चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई यात्री घंटों तक फंसे रहे। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब खेती का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है, तब उन्हें डीजल के लिए भटकना पड़ रहा है। किसानों का कहना था कि यदि समय पर डीजल नहीं मिला तो बोवनी प्रभावित होगी और इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा। उनकी मांग थी कि किसानों के लिए डीजल की अलग व्यवस्था की जाए और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। चक्काजाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बुदनी एसडीओपी रवि शर्मा ने किसानों से चर्चा कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया।

इंदौर-बैतूल हाईवे बचाएगा पानी

इंदौर। सुपर कॉरिडोर से करनावाद तक इंदौर-बैतूल हाईवे न केवल लोगों की राह आसान करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी मददगार साबित होगा। यह हाईवे देश का पहला जल संरक्षण आधारित हाईवे बनने जा रहा है।300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस 26 किलोमीटर लंबे मार्ग की खासियत इसका वैज्ञानिक जल प्रबंधन है। सड़क के दोनों ओर जल निकासी तंत्र, रिचार्ज पॉइंट और स्टॉर्म वॉटर चैंबर बनाए गए हैं, ताकि बारिश की एक-एक बूंद भूजल में समा सके। इसके लिए हाईवे के किनारे पांच बड़े तालाब भी तैयार किए गए हैं, जो 100 बीघा से अधिक क्षेत्र में पानी का संचयन करेंगे। इससे न केवल भूजल स्तर बढ़ेगा, बल्कि आसपास के किसानों को भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूजल स्तर में सुधार होगा।

ग्रामीणों की सुविधा के लिए दोनों ओर सर्विस रोड, 12 बड़े अंडरपास और 100 फीट चौड़े मार्ग बनाए गए हैं। छह बड़े पुल और 25 से अधिक पुलियों के निर्माण से आवागमन आसान होगा। इंदौर के एमआर-10 जंक्शन को इस हाईवे से जोड़ने के लिए चौड़े अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जो अगले छह माह में तैयार हो जाएंगे। 26 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तीन वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया था। वर्तमान में वाहनों को बैतूल हाईवे तक पहुंचने के लिए बायपास से देवगुराड़िया होकर जाना पड़ता है।

मुरैना में 300 परिवारों की जिंदगी ठप

दो महीने से बिजली गुल, आधी रात महापौर बंगले पर फूटा गुस्सा

सच संवाददाता ॥ मुरैना

अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा.. और जहां चाह, वहां राह जैसी कहावतें आज मुरैना शहर की हकीकत बनती दिख रही हैं। वार्ड क्रमांक 3 की छोटी लालौर दलित बस्ती के करीब 300 परिवार पिछले दो महीने से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। बिजली समस्या से परेशान वार्डवासी बार बार शिकायतों के बावजूद राहत न मिलने से आक्रोशित हैं।हालात इतने बिगड़े कि आधी रात को लोग महापौर के बंगले का घेराव करने पहुंच गए। वहां उन्होंने ढाई घंटे तक जोरदार नारेबाजी की लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। थक-हार कर लोग वापस लौट गए। प्रशासनिक उदासीनता ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जनता कब तक ऐसे अंधेरे और उपेक्षा में जीती रहेगी?मुरैना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3 छोटी लालौर की दलित बस्ती पिछले दो महीने से अंधेरे में डूबी हुई है। जहां करीब 300 परिवार बिजली संकट से बुरी तरह परेशान हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो शुक्रवार देर रात आक्रोशित वार्डवासी बिजली घर पहुंचे। लेकिन वहां भी समाधान न मिलने पर वे पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महापौर के बंगले पर पहुंच गए।यहां लोगों ने महापौर निवास के सामने बैठकर ढाई घंटे तक जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। महापौर के शहर में होने की वजह से उनके बेटे सौरव सोलंकी देर रात लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने बिजली कर्मचारियों से बातचीत की थी। उनसे आश्वासन मिलने के बाद लोग अपने-अपने घरों को चले गए।महापौर अपने शहर में आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण निवास पर मौजूद नहीं थीं। निराश लोगों को आखिरकार बिना समाधान के ही लौटना पड़ा। स्थानीय निवासी बलवीर और मनीष पिप्पल ने बताया कि बिजली दो-चार दिन आती है और फिर हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, क्योंकि वार्ड में हैंडपंप न होने से पूरा इलाका बिजली पर ही निर्भर है।बिजली गुल होने पर लोगों को दूर-दराज मोहल्लों से पानी लाना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं मामले को लेकर महापौर शारदा सोलंकी का कहना है कि एक कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से वह नहीं आ पाईं। हमने जनप्रतिनिधि को उनके यहां भेजा और उनसे मिलकर बिजली समस्या जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। समस्या का जल्द निवारण कराया जाएगा।

महापौर और नपा अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त

भोपाल । मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। चुनाव में लगभग डेढ़ वर्ष का समय शेष होने के बावजूद राज्य सरकार ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को आरक्षण संबंधी कार्रवाई के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर एवं अध्यक्ष पद आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसी के तहत आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया का संचालन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने 12 जून को आदेश जारी कर दिए हैं। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग भी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। माना जा रहा है कि सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों स्तरों पर चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कुल पदों का 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है।

रातापानी में त्रिशूल वाला टाइगर, चेहरे पर दोनों ओर महादेव का निशान, देश में सबसे अनोखा बाघ

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

राजधानी भोपाल से सटे रातापानी टाइगर रिजर्व में घूम रहा एक यंग टाइगर इन दिनों चर्चा में है। ये शेर अपने शरीर पर बनी त्रिशूल की दुर्लभ आकृति की वजह से फेमस हो रहा है।टाइगर टी-1236 के गालों पर त्रिशूल की अनोखी आकृति है और यह अनोखी आकृति इसके चेहर पर दोनों ओर एक समान है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक संभवत: यह पहला बाघ है, जिसके दोनों गालों पर त्रिशूल का निशान हैं।टाइगर की पहचान उनके चेहरे के आसपास और शरीर पर बनी धारियों से होती है। यही वजह है कि अब टाइगर की पहचान त्रिशूल और भगवान शंकर से जोड़कर देखी जा रही है। वन विभाग इसका नामकरण भी करा रहा है और इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। संभावना है कि इस टाइगर को त्रिशूल टाइगर नाम दे दिया जाए।औबेदुल्लागंज के डीएफओ हेमंत रायकवार कहते हैं, टाइगर

के चेहरे और शरीर पर धारियों से बनने वाली आकृति आम हैं। लेकिन चेहरे पर बनी त्रिशूल की आकृति ने इसे पर्यटकों के बीच फेमस कर दिया है। देश में पहले राजस्थान के रणथंभौर और मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस तरह के बांध देखे गए थे, जिनके एक साइड पर त्रिशूल जैसा निशान था, लेकिन संभवत: यह देश में पहला बाघ है, जिसके दोनों गालों पर एक समान त्रिशूल के निशान हैं। हेमंत रायकवार कहते हैं कि यह पिछले डेढ़ सालों से रातापानी टाइगर रिजर्व में घूम रहा है।रातापानी टाइगर रिजर्व में घूम रहे टाइगर 1236 का जन्म केरवा के जंगलों में हुआ है। ये बाघिन 123 की संतान है, जो केरवा में घूमती रही है। केरवा में मां से अलग होकर टाइगर 1236 भटकते हुए रातापानी टाइगर रिजर्व में पहुंच गया और अब इसने रातापानी में अपनी स्थायी टेरेटरी बना ली है। सफारी के दौरान यह बाघ आमतौर पर वन्यजीव प्रेमियों को आसानी से दिखाई दे जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञ आमेय विक्रय सिंह कहते हैं, यह जंगल में बेखौफ घूमता है और पर्यटकों की सफारी वाहनों को देखकर भी बिलकुल नहीं घबराता। डीएफओ के मुताबिक, टाइगर के शरीर पर बनी धारियां या पट्टियां ही हर टाइगर की अलग पहचान बनाती हैं। इसके जरिए ही काउंटिंग के दौरान टाइगर की पहचान कर पाना संभाव हो पाता है और ज्यादातर इसी आधार पर टाइगर का नामकरण होता है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुदेश बाघमारे कहते हैं, दुनिया में किसी भी दो बाघों का धारियों का पैटर्न एक समान नहीं होता। यह ठीक इंसानों के हाथों की लकीरों या फिंगर प्रिंट्स के समान होती हैं।

मध्यप्रदेश में तबादलों का आखिरी दिन आज, बढ़ सकती है समय सीमा

भोपाल । मध्यप्रदेश में तबादलों के लिए निर्धारित अवधि का आज अंतिम दिन है, लेकिन कई विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में शासन स्तर पर तबादलों की समय-सीमा को एक सप्ताह तक बढ़ाने पर विचार किए जाने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो लंबित प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए विभागों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। मानसून से पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तबादलों पर लगी रोक में शिथिलता देते हुए 15 जून तक स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागों को निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। जिला स्तर पर तबादलों के अधिकार प्रभारी मंत्रियों को सौंपे गए थे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से अनुमोदन अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद कई विभाग अंतिम तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तैयारियां जारी हैं, जबकि राजस्व विभाग ने हाल ही में पटवारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी दिखाते हुए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किए हैं। विभाग ने प्रभारी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं।